

प्रेषक,

बी०आर०टम्टा,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,  
सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग- 1 देहरादून दिनांक 19 मार्च, 2007  
विषय-चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिये सहकारी सहभागिता योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋणों पर राजकीय अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 4931/नियो०/सहभागिता/2006-07/ दिनांक 14.12.2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 में सहकारी सहभागिता योजना के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों, बी०पी०एल० परिवारों एवं सामान्य कृषकों को अल्पकालीन एवं मध्यकालीन/ दीर्घकालीन/आवास ऋणों पर लागू ब्याज दरों के सापेक्ष भारत सरकार/नाबार्ड से 2 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति के पश्चात राज्य सरकार द्वारा योजनान्तर्गत वहन किये जाने वाले ब्याज दरों के अनुदान की प्रतिपूर्ति हेतु रु० 200.00 लाख (रु० दो करोड़ मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) उक्त धनराशि का उपयोग शासनादेश संख्या 233/2005/XIV-1/2005 दिनांक 28.4.2005, शासनादेश संख्या 359/2006/XIV-1/2006 दिनांक 28.5.2006 तथा शासनादेश संख्या 895/XIV-1/2006 दिनांक 17.10.2006 एवं समय समय पर संशोधित शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार ही किया जायेगा।

(2) निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना महालेखाकार (लेखा) कार्यालय, उत्तराखण्ड को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम व बाउचर संख्या लेखाशीर्षक तथा आहरण की तिथि सहित सूचित करने का उत्तरदायित्व होगा।

(3) इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाय।

(4) उक्त वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि उक्त धनराशि केवल इसी योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ऋणों पर देय ब्याज के राज्यांश के अनुदान के रूप में ही प्रतिपूर्ति की जायेगी तथा किसी ऐसे मद पर धनराशि व्यय न की जाय, जो योजना में स्वीकृत नहीं है।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्ही मदों पर किया जाए, जिसके लिये स्वीकृति दी जा रही है। यदि उसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद में किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिये व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा उनसे अनुशासनिक कार्यवाही करते हुये अप्राधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का योजनावार व्यय विवरण प्रत्येक माह या उसके अगले माह की 5 तारीख तक बी0एम0-13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग/शासन तथा महालेखाकार कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

(7) उक्त व्यय शासन के वर्तमान सुसंगत आदेशों/निर्देशों के अनुसार किया जाएगा तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि उक्त धनराशि किसी ऐसे कार्य/मद पर व्यय न की जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन/राज्य अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित है। वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित सुसंगत नियमों का अनुपालन किया जाय।

(8) उक्त योजना का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर तदनुसार व्यय 31.3.2007 तक सुनिश्चित कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करायेगे तथा अवशेष धनराशि 31.3.2007 को शासन को समर्पित की जाय।

उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-07 के अनुदान संख्या 18 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2425-सहकारिता-00-800-अन्य व्यय-आयोजनागत-13-सहकारी सहभागिता योजना-00-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामें डाला जायेगा।

2.यह आदेश वित्त विभाग की अशा0 पत्र संख्या-640/वित्त अनुभाग-4 /दिनांक 12.3.2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(बी0आर0टम्टा)  
अपर सचिव।

संख्या।20 (1)/XIV-1/2006 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1.महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
- 2.संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय (बैकिंग प्रभाग) नई दिल्ली।
- 3.सचिव, मुख्य मन्त्री कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन।
- 4.निजी सचिव, मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
- 5.वित्त अनुभाग-4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 6.मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।
- 7.वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा उत्तराखण्ड।
- 8.निर्देशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
- 9.सगरस्त जिला सहायक निबन्धक,सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
- 10.गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
(वीरेन्द्र पाल सिंह)  
अनुसचिव।